पंचदश

बिहार विधान-सभा

दशम् सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार,तिथि 10 श्रावण, 1935 (श0) / 01 अगस्त, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या-97

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	27
(2) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	16
(3) कृषि विभाग	..	..	12
(4) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	11
(5) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	10
(6) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	17
(7) सहकारिता विभाग	..	..	04
		कुल योग ..	97

नालों की सफाई

*280. श्री जनार्दन सिंह ''सीग्रीवाल''--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा नगर परिषद क्षेत्र के खनुआ नाला की सफाई दस वर्षों से नहीं हुई है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खनुआ नाला एवं छपरा शहर के अन्य नालों की सफाई जनहित में शीघ्र कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करवाना

*281. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार में पैक्सों को अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला सहकारिता बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि पन्द्रह दिनों तक दिए गए ऋण पैक्सों द्वारा वापस नहीं करने पर सूद देना पड़ता है, लेकिन एस०एफ०सी० बिहार द्वारा दो महीने के बाद पैक्स को भुगतान किया जाता है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एस०एफ०सी० द्वारा समय पर पैक्सों को पैसा भुगतान करवाने तथा विलम्ब होने पर एस०एफ०सी० द्वारा सूद सहित राशि भुगतान करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाइट की व्यवस्था

*282. डॉ० दाउद अली--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमरांव अंसार कॉलोनी चौक के पास, शहीदमल चौक के पास, छठिया पोखरा पार्क के पास, रेलवे स्टेशन के सामने सुपर मैक्स लाइट नहीं होने से आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थलों पर सुपर मैक्स लाइट की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल मुहैया कराना

*283. श्री जितेन्द्र कुमार राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के कुछ प्रखंडों में भू-जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाये जाने के कारण उन्हें आर्सेनिक प्रभावित घोषित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि मढ़ौड़ा प्रखंड के पंचायत मुबारकपुर, भुआलपुर, ओल्हनपुर, माधोपुर, बड़हरिया, बहुआरा पट्टी, नरहपरपुर, रसुलपुर, हथिसार, जोड़ा इसरौली, मिर्जापुर, शिल्हौड़ी, मढ़ौड़ा नगर पंचायत तथा नगर प्रखंड के पंचायत जगदीशपुर, तकिया, तुजारपुर, खैरा, नगरा, काठीपुर, अफौर, धूपनगर इत्यादि पंचायतों के अधिकांश टोलों में भू-जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित पंचायतों में आर्सेनिक की जांच कराकर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण-पूर्ण कराना

*284. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास, घोघरडीहा एवं मधेपुर प्रखंडों में आजतक मुख्य मंत्री चापाकल योजनान्तर्गत चापाकल निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, यदि हां, तो सरकार कबतक उक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*285. श्री सोनेलाल हेम्ब्रम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग स्थित न्यू यारपुर, जक्कनपुर, जनता रोड, सरिस्ताबाद की आबादी 50,000 की है, परन्तु इतनी आबादी होने के बावजूद एक भी सार्वजनिक सामुदायिक भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि सामुदायिक भवन नहीं रहने के कारण यहां के नागरिकों को अपने पुत्र-पुत्रियों के शादी एवं उत्सव समारोह जैसे कार्यक्रम करने में काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यहां के नागरिकों को कठिनाई को देखते हुए सामुदायिक भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*286. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मौजा दीघा सर्वे थाना नं० फुलवारी थाना संख्या 01, तौजी संख्या 5070, खाता संख्या 14, प्लॉट सं० 5403, 5412 कुल रकबा 96 डिसमिल का भू-अर्जन तथा मुआवजा का भुगतान भू-स्वामी को नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि को बगैर भू-अर्जन के ही बियाडा द्वारा निजी कम्पनी को आवंटित कर दिया गया है तथा उक्त कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य भी किया जा रहा है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामले की जांच करवाकर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क की मरम्मती

*287. श्री जय कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बख्तियारपुर नगर पंचायत के वार्ड नं० 6 स्थित मध्य विद्यालय के निकट नाले का पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पानी निकासी का उपाय एवं पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मती करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक ?

राशि विमुक्त करना

*288. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखंडान्तर्गत, विक्रमगंज शहर के इर्द-गिर्द सेमरा, नोनहर एवं बसगीतिया आदि ग्रामों में पेयजलापूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ रु० की स्वीकृति योजना दिनांक 27 जनवरी, 2010 से विभागीय सचिव के पास राशि विमुक्ति हेतु लम्बित रहने से आमजन को पेयजल मयस्सर नहीं हो रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि की विमुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*289. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर अंचल के डोइला गांव में विनवा टोली से हाहवा तक नाला को भरकर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण डोइला छनिया चवर में जल का जमाव हो जाता है एवं 25 वर्षों से किसानों का फसल बर्बाद होता आ रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नाला की जमीन को पैमाईस कराकर अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*290. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल--दैनिक समाचार-पत्र में छपे शीर्षक बिना आपूर्ति कराये ही डीलरों ने निकाल ली रकम ''कागज पर ही खरीदारी अनुदान गया जेब में'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र जैसे पावर टीलर, रीपर, सिंचाई पाइप, पम्प सेट आदि आपूर्ति कराने के नाम पर सरकार को लगभग 15 लाख का घाटा लगाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कृषि यंत्र डीलरों ने किसानों को अनुदान दिये बिना ही अनुदान की रकम प्राप्त कर ली है;

(3) यदि उपरोक्त खडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामला में शामिल माँ दुर्गा इन्टरप्राईजेज, राम जानकी इन्टरप्राईजेज, कृषकों इन्टरप्राईजेज, शिवम हार्डवेयर, विकास डीलर्स एवं शिव शक्ति इन्टरप्राईजेज सहित अन्य डीलरों के अलावा कृषि पदाधिकारियों की संलिप्तता की जाँच कराकर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सालय का निर्माण

*291. श्री परमानन्द ऋषिदेव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के रानीगंज प्रखण्ड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय नहीं है, जिससे रोगग्रस्त पशु एवं पशुपालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रानीगंज प्रखण्ड मुख्यालय में पशु चिकित्सालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*292. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 6 जून, 2013 के अंक में छपी खबर ''खुले आसमान के नीचे है 53 हजार टन धान'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले खरीफ मौसम में सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीदे गये धान में से 13 लाख टन धान चावल मिलों को दिया गया है तथा 8 लाख टन धान एस० एफ० सी० के गोदामों में रखा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि किसानों से खरीदे गये शेष 53 हजार क्विंटल धान राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों पर खुले में रखे गये हैं;

(3) यदि उपरोक्त खडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खुले रखे गये 53 हजार क्विंटल धान को सुरक्षित करने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है और कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूर्ण कराना

*293. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008 एवं 2010-11 में 98 पैक्सों में गैसीफायर के साथ मिनी राईस मिल स्थापित करने हेतु 128.00 लाख रुपया विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, परन्तु प०चम्पारण के पीरा खेम पैक्स सहित 70 प्रतिशत पैक्सों में उक्त योजना अधूरी पड़ी है, क्योंकि पैक्सों को सहकारी बैंकों द्वारा उक्त योजना के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत ऋण की राशि मुहैया नहीं कराये जाने के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधूरी योजनाओं की बाधाओं को दूर करते हुये अविलम्ब इसे पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल मुहैया कराना

*294. श्रीमती उषा सिन्हा--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले के परवलपुर प्रखण्ड के शंकरडीह, मई, बिसाई बिगहा, बंगपुर तथा धनावाँ गाँवों में जल स्तर काफी नीचे रहने के कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार शुद्ध जल मुहैया कराने का विचार रखती है ?

जलापूर्ति कराना

*295. श्री अवधेश कुमार राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग न्यू यारपुर-मुहल्ले के पूरब अंतिम छोर पर मीत इलेक्ट्रीक के ठीक पीछे वर्ष 2012 में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा नालन्दा ट्यूबवेल के माध्यम से बोरिंग कराया गया है लेकिन अबतक मोटर नहीं लगाने के कारण यहाँ के निवासियों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे पीने के पानी की किल्लत हो रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में मोटर पम्प लगाकर शीघ्र उक्त बोरिंग को चालू कर जलापूर्ति कराने का विचार रखती है ?

आर्थिक क्षति का औचित्य

*296. श्री अरुण शंकर प्रसाद--स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 6 मई, 2013 को प्रकाशित शीर्षक '' दियारा विकास योजना में छः जिले फिसड्डी'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में पटना सहित 25 जिलों में दियारा विकास योजना संचालित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना में वर्ष 2012-13 में पश्चिम चम्पारण जिला को आवंटित 17.18 लाख रुपये में खर्च शून्य, कटिहार को 18.95 लाख में से खर्च 20 हजार, पूर्णियां को 43.93 लाख में से खर्च 13.93 लाख, बेगूसराय को 18.20 लाख में से खर्च 6 लाख, मधेपुरा को 43.93 लाख में से खर्च 19.46 लाख रुपये ही किये गये हैं, यदि हाँ, तो राशि खर्च नहीं किये जाने के कारण उक्त जिलों के किसानों को आर्थिक क्षति का क्या औचित्य है ?

स्पेन्डल को बनवाना

*297. श्री अम्बिका सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड दुर्गावती में दुर्गावती बाजार में पानी टंकी का स्वीच भाल्व का स्पेन्डल 8-9 महीने से खराब है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्पेन्डल खराब रहने से पानी का स्टाक नहीं हो पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खराब स्वीच भाल्व स्पेन्डल को बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*298. श्री गिरिधारी यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला में भू-लगान की दर 4 रुपये से लेकर 8 रुपये प्रति एकड़ सरकार द्वारा निर्धारित है;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत एक वर्ष से उपरोक्त सरकारी दर के बदले पूरे बाँका जिले में राजस्व कर्मचारियों द्वारा 100 रुपये से 200 रुपये प्रति एकड़ भू-लगान वसूला जा रहा है, जिसकी रसीद की प्रविष्टि अभिलेख में नहीं की जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी दर से अधिक राशि वसूलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य पूरा करवाना

*299. श्री तारकिशोर प्रसाद--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 फरवरी, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''चावल के खरीद में एफ०सी०आई० पीछे'' के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारतीय खाद्य निगम वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य खाद्य निगम से चावल मात्र 10 लाख 47 हजार 853 टन ही खरीदा है जबकि 14 लाख 71 हजार 306 टन चावल खरीदने का लक्ष्य था;

(2) क्या यह बात सही है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय पर चावल की खरीद नहीं करने से धान खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल खरीद का निर्धारित लक्ष्य पूरा करवाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने जा रही है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*300. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 26 जून, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''देख-रेख की कमी, सड़ रहा धान'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखण्ड में पैक्स अध्यक्षों के माध्यम से वर्ष 2012-13 में एस०एफ०सी० गोदाम प्रबंधक द्वारा 31 हजार क्विंटल धान क्रय किया गया जिसमें 16 हजार क्विंटल धान विभिन्न चावल मिलों को भेजा गया, शेष 15 हजार क्विंटल धान की बोड़ियाँ अभी भी खुले आकाश के नीचे पड़ी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि एक महीने से भारी वर्षा के कारण धान सहित धान की बोड़ियाँ सड़कर बर्बाद हो गया है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो 15 हजार क्विंटल धान की बर्बादी के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बीज उपलब्ध कराना

*301. श्री परमानन्द ऋषिदेव--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि रोड मैप में सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक मुख्य मंत्री तीव्र बीज विकास विस्तार योजना है जिसके अन्तर्गत धान, गेहूँ, चना, मसूर का आधार बीज किसानों को राज्य में उपलब्ध कराया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि तिलहन के रूप में पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, सुपौल एवं सहरसा जिला में सूर्यमुखी की खेती बड़े पैमाने पर होती है, परन्तु किसानों को इसके लिये आन्ध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के उत्पादित बीज मनमाने कीमत 400 रुपये से 700 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अदा करनी पड़ती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूर्यमुखी का प्रमाणित बीज खण्ड (1) में वर्णित योजना के तहत बिहार में उत्पादित बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरण करना

*302. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विगत 3 वर्षों से बिहार सहकारिता सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि 3 वर्षों से स्थानान्तरण नहीं होने के कारण बिहार सहकारिता सेवा के राजपत्रित पदाधिकारी वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं; तो क्या सरकार नियमानुसार 3 वर्षों से अधिक से एक स्थान पर पदस्थापित बिहार सहकारिता सेवा के राजपत्रित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । क्योंकि बिहार सहकारिता सेवा के कतिपय राजपत्रित पदाधिकारियों को कार्यहित में यथा--

अधिसूचना सं० 388A, दिनांक 28 जनवरी, 2011, अधिसूचना सं० 1741, दिनांक 13 अप्रील, 2011,

अधिसूचना सं० 4509, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011, अधिसूचना सं० 5605, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011,

अधिसूचना सं० 2181, 2182, 2183, दिनांक 24 मई, 2012, अधिसूचना सं० 1918, दिनांक 24 मई, 2013 एवं अधिसूचना सं० 2407, दिनांक 03 जून, 2013 द्वारा कई पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन किया गया है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं० 434, दिनांक 01 मार्च, 2007 के आलोक में स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में एक बार जून माह में किया जाना है । जून माह समाप्त हो गया है । ससमय स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नियमानुसार की जायेगी ।

दण्डित करना

*303. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला में बगीचा बचाओ अभियान के तहत जिला के सभी प्रखण्डों में जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना के नाम से वर्ष 2012-13 में प्रति प्रखण्ड 1 लाख 98 हजार रुपये अनुदान की राशि किसानों के बीच वितरण के लिये दी गई थी, परन्तु किसानों के बीच अनुदान की राशि वितरण नहीं की गई;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी को दण्डित करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह चालू कराना

*304. श्री आनन्दी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शवदाह गृह को आजतक चालू नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त शवदाह गृह को चालू कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*305. श्री अख्तरुल ईमान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य कराने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग को 26 करोड़ रुपये वर्ष 2010 में दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग द्वारा कार्य करा दिया एवं दिसम्बर, 2012 में नगर विकास मंत्री द्वारा उद्घाटन भी किया गया, परन्तु लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग द्वारा हैण्ड ओभर करने पर नगर विकास विभाग द्वारा टेक-ओभर नहीं लिया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार टेक-ओभर कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

पशु चिकित्सक प्रतिनियुक्त करना

*306. श्री चन्द्रशेखर--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 14 जुलाई, 2013 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''पशु 11 लाख, डॉक्टर महज 17'' के आलोक में क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला में पशुओं की संख्या 11 लाख लेकिन डॉक्टर महज 17 ही हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार अनुमण्डलीय अस्पताल, मधेपुरा सहित जिला के अन्य पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला पथ का निर्माण

*307. श्री (डॉ0) रामानन्द यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा नगर पंचायत के वार्ड नं0 2, गढ़ोचक में श्री जगदीश गुप्त के घर से रेलवे लाइन के मुख्य पथ तक सड़क एवं नाला का निर्माण नहीं हुआ है, बरसात के दिनों में रास्ता जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं नाला का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आपूर्ति नियमित करना

*308. श्रीमती आशा देवी (186)—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् खगौल एवं नगरपालिका, दानापुर में किरासन तेल ठेला भेंडरों द्वारा किरासन तेल की नियमित आपूर्ति नहीं होने से यहाँ के लोगों को किरासन तेल 50-80 प्रति लिटर बाजार से खरीदना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर नियमित आपूर्ति कराने का विचार रखती है ?

हस्तांतरण डीड देना

*309. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत श्री कृष्णानगर कॉलोनी का निर्माण भारत सरकार से प्राप्त ऋण साधारण ब्याज पर भू-अर्जन कर 1960—62 में लगभग 150 मकानों को अल्प आय वर्गीय लोगों के बीच हानि लाभ रहित बिक्री की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1999 में पारित आदेश के बावजूद अबतक राज्य आवास बोर्ड द्वारा अन्तिम हस्तांतरण डीड नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अल्प आय वाले आवंटित गृह स्वामियों को अन्तिम हस्तांतरण डीड देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*310. श्रीमती आशा देवी (186)—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद्, दानापुर के मिथिला कॉलोनी, जजेज कॉलोनी, न्यू मैनपुरा, खरंजा रोड, भट्ठा रोड, मुबारकपुर, कृषि फार्म एवं बी0बी0 गंज मोड़ से नया टोला तक एवं रामजयपाल पथ अन्तर्गत अर्पणा बैंक कॉलोनी फेज II विभिन्न मुहल्लों में जल-जमाव की भीषण समस्या है, यदि हाँ, तो जल निकासी हेतु सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*311. श्री जितेन्द्र कुमार राय—दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 30 अप्रील, 2013 के अंक में छपी खबर ''मिट्टी जाँच में सूबे के डेढ़ दर्जन जिले फिसड्डी'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में सरकार द्वारा राज्य के सभी किसानों को स्वायल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना शुरू की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि अधिकारियों की उदासीनता के कारण पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य के खगड़िया जिला को छोड़कर मिट्टी जाँच का लक्ष्य किसी भी जिले में पूरा नहीं की गयी, जिसके कारण लाखों किसान इस योजना के लाभ से वंचित हो गये;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त योजना की विफलता के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*312. श्री प्रदीप कुमार : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखण्ड वारिसलीगंज में डॉ० किसान भवन नहीं है जिसके कारण कृषकों एवं कृषि विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड वारिसलीगंज में डॉ० किसान भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है; हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*313. श्री गोपालजी ठाकुर : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बेनीपुर नगर परिषद् क्षेत्र के आशापुर धरौड़ा पथ के नजदीक से अशोक ठाकुर के घर होते हुए महाधिराजा धिराज मंदिर तक बहेड़ा पानी टंकी से मथन साह पोखर होते हुए पांचियाही पुल पी० डब्लू० डी० तक एवं दुखराम संस्कृत उच्च विद्यालय से मदन ठाकुर के घर होते हुए दुर्गास्थान तक तथा दुखराम मध्य विद्यालय से बाबू नारायण झा के घर तक सड़क एवं नाला नहीं रहने के कारण लोगों को काफी कठिनाई हो रही है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जनहित में उक्त सड़क एवं नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य

*314. श्री मंजीत कुमार सिंह : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज ने अपने ज्ञापांक 1751, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा गोपालगंज जिला के हथुआ, सिंधवलिया एवं बैकुंठपुर प्रखंडों में महादलित टोले में सम्पर्क पथ हेतु भूमि अर्जित करने हेतु 33 लाख 27 हजार 632 रु० की आवंटन की माँग उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सचिव एवं आयुक्त, सारण प्रमण्डल से की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 से अबतक हथुआ, सिंधवलिया एवं बैकुंठपुर प्रखंडों में से एक भी महादलित टोले में सम्पर्क पथ हेतु भूमि अर्जित नहीं की गई है, जिससे आवागमन बाधित है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, सम्पर्क सड़क योजना के तहत अबतक राशि उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य क्या है ?

कार्रवाई करना

*315. श्री राज कुमार राय : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अंचल के मौजा भरवात किया के तौजी नं० 4637 में जमाबंदी नं० 107 का सृजन आमद जमाबंदी सं० 34 भिन्न खाते खेसरे से की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि आमद जमाबंदी सं० 34 का ओभर राइटिंग कर पूर्णरूपेण काटकर जमाबंदी सं० 107 का सृजन किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि जमाबंदी सं० 107 बिना भौतिक दखल के ही दर्ज कर दिया गया तथा दाखिल खारिज केस संख्या 932/2001-2002 की संचिका अंचल कार्यालय से गायब कर दी गयी है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आमद जमाबंदी सं० 34 से भिन्न जमाबंदी सं० 107 को रद्द कर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नक्शा उपलब्ध कराना

*316. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में जमीन का नक्शा उपलब्ध कराने हेतु एक मात्र प्रेस गुलजारबाग, पटना में स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रेस में आधारभूत संरचना एवं कर्मचारी की कमी के कारण पूरे प्रदेश के नागरिकों को ससमय नक्शा नहीं मिल पाता है, तथा नक्शा की मूल प्रति को आम नागरिकों को दिया भी नहीं जाता है और केवल छायाप्रति के लिए आवेदन प्राप्त किये जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रेस का आधुनिकीकरण कर हर प्रकार का नक्शा आम जनता को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गंदगी का औचित्य

*317. श्री जय कुमार सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एक तरफ पटना का विकास महानगर के रूप में हो रहा है, परन्तु कचरा प्रबंधन की योजना नहीं रहने के कारण शहर में गन्दगी व्याप्त है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नाला का निर्माण

*318. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडिया नगर पंचायत में नाला निर्माण नहीं होने के कारण जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का समायोजन

*319. श्री रामदेव महतो--क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के राजनगर व्यापार मंडल को राईस मिल गैसीफायर एवं मशीन खरीदने हेतु 6.00 लाख रुपया वर्ष 2011 में विभाग द्वारा अग्रिम राशि दी गई है एवं मशीन की खरीद की, परन्तु अभीतक उक्त राशि का समायोजन लंबित है, यदि हाँ, तो उक्त राशि समायोजन हेतु सरकार कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि समेकित सहकारी विकास परियोजना मधुबनी अंतर्गत राजनगर व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण तथा चावल मिल गैसीफायर की समेकित योजना कुल 24.20 लाख रु० की स्वीकृति वर्ष 2010 में दी गई है । उक्त योजना अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु 7.00 लाख रु० गैसीफायर एवं चावल मिल संयत्र हेतु 15.00 लाख रु० एवं व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी के रूप में 2.00 लाख रु० कर्णांकित थे । उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राजनगर व्यापार मंडल को भवन निर्माण मद में 6.30 लाख रु० तथा संयत्र मद में 7.60 लाख रु० कुल 13.90 लाख रु० उपलब्ध कराये गये हैं एवं शेष 10.30 लाख रु० समिति के विशेष खाता में जमा है । उपलब्ध कराये गये राशि के विरुद्ध कराये गये निर्माण कार्य (मापी पुस्तिका के आधार पर) के अनुरूप 5,95,989.00 रु० का समायोजन हो चुका है । तथा शेष 34,011.00 रु० के प्रमाणक समिति स्तर पर समायोजन हेतु शेष है । व्यापार मंडल द्वारा संयत्र आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को 7.60 लाख रु० अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया गया है । योजना पूरी होने के उपरान्त अंकेक्षण के आधार पर पूर्ण समायोजन किया जा सकेगा ।

जलापूर्ति चालू कराना

*320. श्री शिवजी राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा प्रखंड में विगत एक वर्ष पूर्व में जलमीनार एवं मधुबन प्रखंड में 7 माह से जलमीनार बनकर तैयार है एवं उक्त दोनों प्रखंडों में जलापूर्ति का कार्य को 10 माह पूर्व में ही संपन्न करा लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छः माह पूर्व में ही इसकी शिकायत कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्वी चम्पारण के प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पत्र दिया गया है बावजूद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में जलापूर्ति चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड वितरित करना

*321. श्री छोटेलाल राय--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में वधवा आयोग द्वारा सभी जन-वितरण प्रणाली के दुकानदारों को बराबर-बराबर राशन कार्ड का वितरण हेतु अनुशंसा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड में आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा सभी दुकानदारों को बराबर-बराबर राशन कार्ड का वितरण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वधवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में सोनपुर प्रखण्ड के जन-वितरण प्रणाली के दुकानदारों को बराबर-बराबर राशन कार्ड वितरित कराने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

*322. श्री अब्दुलबारी सिद्दीकी--दिनांक 27 मई, 2013 एवं 28 मई, 2013 को स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक क्रमशः ''संक्रमित सांढ़ों से हो रहा कृत्रिम गर्भाधान'' एवं ''स्वस्थ सांढ़ों पर बीमारी का खतरा'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार लाइव स्टॉक डेवलेपमेंट एजेंसी, पटना द्वारा जिन सांढ़ों का संधारण कर उसका स्ट्रॉज उत्तम किस्म के नस्ल के लिए कृत्रिम गर्भाधान कराने हेतु जिलों को दिया जाता है, उनमें से 50 फीसदी सौंढ़ आर० डी०डी०एल० कोलकता के रिपोर्ट के अनुसार संक्रमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संक्रमित सौंढ़ों के स्ट्रॉज के कारण गायों में बांझपन के साथ कई बीमारियाँ होती हैं एवं प्रजनन के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें संक्रमण ट्रांसमिट कर जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो संक्रमित सौंढ़ों से स्ट्रॉज का वितरण करने का क्या औचित्य है तथा सरकार इसकी रोकथाम के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

जमीन उपलब्ध कराना

*323. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया प्रखण्ड के माडर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नं० 4 में 115 महादलित परिवार और वार्ड नं० 7 में 70 महादलित परिवार को अबतक तीन डिसमल जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उन महादलित परिवारों को घर बनाने के लिए तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिष्ठापित करना

*324. श्री अजय प्रताप—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई विधान–सभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में सोलर चालित 10, डीजल चालित 20, ऊर्जा चालित 38 स्थानों पर पेयजल आपूर्ति हेतु पम्प अधिष्ठापित करने का प्रावधान किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा इस संदर्भ में मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पत्र के माध्यम से दिसम्बर, 2012 में शिकायत करने के बावजूद भी अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोलर चालित, डीजल चालित एवं ऊर्जा चालित पेयजल पम्पों को अधिष्ठापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवागमन बहाल करना

*325. श्री पवन कुमार जायसवाल—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखंड के बेरवा से माध्य विद्यालय, बरेवा होते फुलवरिया जाने वाले मुख्य पथ पर विगत 20 वर्ष पूर्व से ईंट सोलिंग था तथा वर्ष 2012–13 में मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा पी०सी०सी० सड़क की स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण हो चुका है, परन्तु पूर्व मुखिया द्वारा उक्त रास्ते को अपने बाउंड्री में मिला लिया गया जिस कारण बच्चों/ग्रामीणों का विद्यालय आने का मुख्य रास्ता बंद हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्रामीणों के आवेदन को संलग्न करते हुए अपने पत्रांक 128, दिनांक 8 जून, 2013 द्वारा जिलाधिकारी/अपर समाहर्ता सहित सभी पदाधिकारीगण को शीघ्र हस्तक्षेप कर संलिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा था, परन्तु अभीतक कार्रवाई नहीं हुई ;

(3) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ में अतिक्रमित भाग को कब्जा करने के मामले में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराकर आवागमन बहाल कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?

अवैध निकासी की जाँच

*326. डॉ० दाउद अली—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत कंकड़बाग स्थित वार्ड नं० 43, एम०आई०जी० फ्लैट सं० 69 हनुमान नगर के पश्चिम जीरो चैम्बर की सफाई वर्षों से नहीं की गयी है और वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में कार्यपालक पदा० द्वारा इस कार्य हेतु कर्णांकित राशि की निकासी की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चैम्बर के सफाई नही होने से एम०आई०जी० के फ्लैटों में जल–जमाव बना रहता है, जिससे महिला एवं बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जीरो चैम्बर की सफाई वर्षात पूर्व कराते हुए अवैध निकसी की जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*327. श्री अशोक कुमार सिंह (क्षे०224)— क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज के नगर पंचायत में सार्वजानिक शौचालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सार्वजनिक शौचालय नहीं रहने से नगर के गरीब तबके के लोगों एवं शहर में बाहर से आने–जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रफीगंज नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*328. डॉ० इजहार अहमद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अंचल स्थित सुपौल बाजार के हटियागाछी हाट की भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो उक्त हाट भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

दोषियों पर कार्रवाई

*329. श्री प्रेम रंजन पटेल—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत सुर्यगढ़ा प्रखंड के महम्मदपुर पंचायत में स्वजल धारा योजना के तहत् जलापूर्ति योजना का कार्य विगत् 10 वर्षों से चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति योजना में स्वीकृत राशि 45 लाख रु० की निकासी कार्यपालक अभियंता द्वारा कर योजना को पूर्ण नहीं किया जा सका है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जलापूर्ति योजना पूर्ण नहीं होने से स्थानीय लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महम्मदपुर पंचायत के स्वजल धारा योजना को पूर्ण कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, अगर हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*330. श्री शशिभूषण हजारी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी तथा बिरौल प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में मिण्टुआ, तिकेश्वर, कुशेश्वर स्थान, महिसौर सहित 32 पंचायतों में चापाकल गाड़ा गया है, परन्तु बाकी चापाकल खराब एवं बंद पड़े हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सभी पंचायतों के बंद पड़े चापाकल को चालू कराकर दोषी संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*331. श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड समस्तीपुर के ग्राम–दादपुर, ग्राम–विक्रमपुर बान्दे एवं प्रखंड ताजपुर के ग्राम–आधार में वर्ष 2010–11 से ही लघु ग्रामीण पाइप लाइन पेय जलपूर्ति योजनान्तर्गत केवल बोरिंग कर छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजनाओं को कबतक पूर्ण कराकर आम जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है ?

नाला का निर्माण

*332. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के कसबा रानी सती चौक से महावीर चौक, गरीबचौक तक सड़क के दोनों तरफ नाला नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान पर नाला नहीं रहने के कारण सड़क के दोनों किनारों पर पानी सालोंभर जमा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर सड़क के दोनों किनारों पर बड़ा नाला का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच केन्द्र की स्थापना

*333. श्री अशोक कुमार सिंह (क्षे0 224)—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर एवं रफीगंज प्रखंड में मिट्टी जाँच केन्द्र नहीं है, यदि हां, तो प्रावधान के बावजूद उक्त दोनों प्रखंडों में मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

आवारा कुत्तों पर नियंत्रण

*334. श्री अवनीश कुमार सिंह——स्थानीय हिन्दी दैनिक में दिनांक 3 जून, 2013 को प्रकाशित समाचार शीर्षक 'एक साल में सात लाख लोगों को कुत्तों ने काटा' के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की कारगर व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्ष 2012 में सात लाख लोगों को कुत्तों ने काटा है, यदि हाँ, तो आवारा कुत्तों पर कारगर नियंत्रण के लिए सरकार का क्या कार्य योजना है ?

कूपन का वितरण

*335. श्री जवाहर प्रसाद——क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि——

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर परिषद् क्षेत्र में मई, 2013–14 के राशन उठाव हेतु उपभोक्ताओं को कूपन वितरण अभीतक नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कूपन वितरण नहीं होने के कारण दो माह से लोगों को राशन एवं किरासन तेल की आपूर्ति बन्द हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कूपन वितरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना करना

*336. डॉ0 इजहार अहमद——क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल में पशु अस्पताल नहीं रहने के कारण वहा पशुओं का समुचित इलाज नही हो पा रहा है, यदि हां, तो सरकार वहां की जनता के हित में कबतक पशु अस्पताल की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*337. श्री ललित कुमार यादव——दिनांक 17–23 जून, 2013 के हिन्दी साप्ताहिक समाचार–पत्र में प्रकाशित 'भूख से मर रहे लोग, सड़ रहा है अनाज' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखण्ड के सुरहाचट्टी में एस0एफ0सी0 के

पदाधिकारियों की लापरवाही से एक लाख छः हजार क्विंटल धान खुले खेत में सड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*338. श्रीमती उषा सिन्हा---क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले के परवलपुर प्रखंड के मर्दन बिगहा ग्राम में पाइप लाइन जलापूर्ति-सह-मीनार योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2008-09 से चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना में पाइप लाइन विस्तार की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभीतक जल मीनार से जलापूर्ति प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त गाँव पेयजल से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पाइप लाइन विस्तार की स्वीकृति देकर जलापूर्ति चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापना नहीं करने का औचित्य

*339. श्री वीरेन्द्र सिंह---क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखण्ड के महुरात पंचायत में चिकित्सा के अभाव में पशुओं की मृत्यु हो जाती है, यदि हाँ, तो उक्त पंचायत में अभीतक पशु चिकित्सालय की स्थापना नहीं करने का क्या औचित्य है ?

संख्या में वृद्धि के उपाय

*340. डॉ0 अच्युतानन्द---दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 01 मई, 2013 के अंक में छपी खबर "गौ प्रजाति की संख्या में भारी कमी" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि 18वीं पशु गणना में राज्य के 22 जिलों में गौ प्रजाति की संख्या में 7 लाख की कमी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिले में अप्रत्याशित रूप से गौ प्रजाति में 2.5 लाख की कमी हुई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में गौ प्रजाति की संख्या में ह्रास होने के कारणों की जाँच कराते हुये गौ प्रजाति की संख्या में वृद्धि के उपायों पर विचार करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*341. श्री कुमार शैलेन्द्र---क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के खरीक अंचल में अंचलाधिकारी का पद जनवरी, 2012 से रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त रिक्त पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

अनुपालन कराना

*342. श्री रामप्रवेश राय-- क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 181(4), दिनांक 26 अप्रील, 2012 द्वारा बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों का समायोजन राजस्व कर्मचारी के पद पर करने का आदेश दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अभीतक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विभागीय आदेश का अनुपालन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

काबिल लगान का कार्य

*343. श्री कुमार शैलेन्द्र-- क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता द्वारा ग्राम-रायपुर मौजा खाता नं० 722, खेसरा नं० 1237, 1223,1524,1335 खाता नं० 933,930 खेसरा नं० क्रमश: 1453,14 एवं खाता सं० 923 खेसरा नं० 1616 इत्यादि भूखंडों का काबिल लगान का कार्य नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

चापाकल को गाड़ना

*344. श्री सदानन्द सिंह-- क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रत्येक विधायक के अनुशंसा पर उनके चुनाव क्षेत्र में प्रत्येक पंचायतों में पाँच (5) चापाकल गाड़ने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के आलोक में प्रश्नकर्ता द्वारा भी दिनांक 27 फरवरी, 2013 को अपने पत्रांक 1772 द्वारा भागलपुर जिला के कहलगाँव क्षेत्र हेतु सूची कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल (पूर्वी) भागलपुर को दे दी गई थी;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त सूची के अनुरूप भागलपुर जिले के संहौला प्रखंडान्तर्गत सिलहन-खजुरिया पंचायत, धुआवे पंचायत में डी०टी० योजनान्तर्गत (डीप चापाकल) में अनुशंसित छह (6) चापाकल अबतक नहीं गाड़े गये हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बचे हुए चापाकल को गाड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाइट नहीं लगाने का औचित्य

*345. श्री अरुण कुमार सिन्हा-- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिसम्बर, 2005 ई० में राजधानी के सभी विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने के सरकार का निर्णय का अनुपालन आजतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो राजधानी के सभी पोलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाये जाने का क्या औचित्य है ?

लाइसेन्स नहीं देने का औचित्य

*346. श्री भूमेन्द्र नारायण सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पी०डी०एस० का लाइसेन्स अब पैक्सों को देने का निर्णय वर्ष 2011 में लिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गोरियाकोठी विधान-सभा क्षेत्र के गोरियाकोठी प्रखंड अन्तर्गत हरपुर, सादीपुर पैक्स के अब तक पी०डी०एस० का लाइसेन्स नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो प्रावधान के बावजूद गोरियाकोठी विधान-सभा में पी०डी०एस० का लाइसेन्स पैक्सों को नहीं देने का क्या औचित्य है ?

ऑन लाइन कराना

*347. श्री गिरिधारी यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर-2 के सभी भू जमाबंदी को ऑन लाइन करने का निर्णय लिया गया है परन्तु उक्त निर्णय का उल्लंघन कर बाँका जिला प्रशासन द्वारा रैयतों को सूचना प्रकाशित कर सूचित किया गया है कि अपनी जमाबंदी के बारे में फॉर्मेट में भरकर सूचना अंचल को प्रस्तुत करें जिसके कारण एक ही जमीन के बारे में कई लोग फॉर्मेट में सूचना भरकर उपलब्ध करा रहे हैं जिससे जिले में नया भू-विवाद शुरू हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रजिस्टर-2 के अभिलेख को ही ऑन लाइन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कैनालों की सफाई

*348. श्री रामदेव महतो-- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधुबनी में नगर परिषद् अन्तर्गत जल निकासी का मुख्य नाला क्रमशः वाटसन कैनाल, राज्य कैनाल एवं किंग्स कैनाल में कचरा भर जाने से विगत दो वर्षों से जल निकासी अवरुद्ध हो गया है जिससे आमजनों के घरों में पानी भरा रहता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब उक्त कैनालों की सफाई कराकर जल निकासी कराने का विचार रखती है ?

रिक्त पदों को भरना

*349. श्री तार किशोर प्रसाद-- क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार राजस्व जिला में अंचल निरीक्षक का स्वीकृत पद 16 के विरुद्ध मात्र 1 अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी का स्वीकृत पद 238 के विरुद्ध मात्र 67 राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं, यदि हाँ, तो उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

राशि खर्च करने का औचित्य

*350. श्री अजित कुमार-- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत काँटी नगर पंचायत के विकास हेतु सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के अन्दर विभिन्न मद में दो करोड़ पचास लाख रु० उपलब्ध कराया गया है, यदि हाँ, तो उक्त राशि को खर्च नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

दोषी पर कार्रवाई

*351. श्री विक्रम कुँअर--दिनांक 23 मई, 2013 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित '' मिल मालिकों ने हड़पे चावल'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12 में सीधे किसानों से प्राथमिक साख सहयोग समिति (पैक्स) और राज्य खाद्य निगम के माध्यम से 21.59 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस धान की कुटाई के लिये 1,422 चावल मिलों को राज्य खाद्य निगम द्वारा सुपुर्द किया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि किसानों से खरीदे गये धान से 67 फीसदी की दर से तैयार चावल की कुल मात्रा 14.66 लाख मीट्रिक टन होनी थी, परन्तु अभीतक 11.79 लाख मीट्रिक टन चावल ही भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति की गयी है ;

(4) क्या यह बात सही है कि 46 हजार मीट्रिक टन चावल मिल मालिकों द्वारा नहीं दिया गया है ;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जल की निकासी

*352. श्री दिनकर राम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के गर्दनीबाग आवासीय कॉलोनी के पानी की निकासी नहीं रहने से सम्पूर्ण कॉलोनी सालो भर गंदे पानी से जलमग्न रहता है, जिससे आवासियों को काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जल निकासी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति चालू कराना

*353. श्री अम्बिका सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत प्रखण्ड दुर्गावती, रामगढ़ एवं नुआँव में जलापूर्ति योजना 2008-09 में स्वीकृत हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक एवं विभाग के लापरवाही से आजतक मिनी जलापूर्ति चालू नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मिनी जलापूर्ति को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शीतलीकरण यंत्र की स्थापना

*354. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत सरमेरा प्रखंड मुख्यालय में दुग्ध शीतलीकरण हेतु भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2007-08 में पूरा हो चुका है, लेकिन आजतक उक्त भवन में शीतलीकरण यंत्र की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त निर्मित भवन में शीतलीकरण यंत्र की स्थापना कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का मूल्य दिलाना

*355. डॉ० उषा विद्यार्थी --क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिहटा प्रखडान्तर्गत ग्राम-अमहारा में बियाडा द्वारा अधिग्रहित जमीन की उचित मूल्य भुगतान हेतु विभागीय सचिव द्वारा पत्रांक 923, दिनांक 18 मई, 2010 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुपालन में आजतक संबंधित किसानों को जमीन का मूल्य नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार संकल्प के आलोक में किसानों को जमीन का मूल्य दिलाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*356. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड के नदरपुर, कुरमावां, खरांटी, धोड़ाघाट, पचरतन, पट्टी, डोभी, नावाडीह, बारी बजौरा, नीमा, कुरा-बीजा एवं अंगरा, शेरघाटी प्रखण्ड के चांपी, श्रीरामपुर, डाबचिरैया, गोपालपुर, कचौड़ी बेला, चेरकी, चिताबकल एवं बार तथा आमस प्रखण्ड के रामपुर, बड़की चिलमी, झरी, आमस, मवि, करमडीह, कलवन, अकौना एवं महुआवां पंचायतों में गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे चले जाने से पेयजल की असुविधा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शेरघाटी, डोभी एवं आमस के उपरोक्त वर्णित पंचायतों में जमीन के अन्दर पहाड़ मिल जाने से साधारण ट्यूबवेल नहीं चल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेरघाटी, डोभी एवं आमस प्रखण्डों में विशेष अभियान चलाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण

*357. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के नगर पंचायत में काली मंदिर से नन्दा बर तक सड़क एवं नाला लोदीशहीद, शाहीन लाईब्रेरी से गढ़ महल्ला होते हुए बुढ़ी नदी तक सड़क एवं नाला, रमना महल्ला से बुढ़ी नदी तक नाला, नई बाजार महादलित टोला से बुढ़ी नदी तक सड़क एवं नाला, लीपगंज चट्टी महल्ला में सड़क एवं नाला नहीं रहने से बरसात में जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त वर्णित सड़कों एवं नालों का निर्माण नहीं होने से नगरवासियों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों पर नागरिकों की सुविधा हेतु नाला एवं सड़क बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*358. श्री वीरेन्द्र सिंह--स्थानीय हिन्दी दैनिक में दिनांक 3 जून, 2013 को प्रकाशित समाचार शीर्षक ''मैदान में सड़ रहा हजारों क्विंटल धान'' के संदर्भ में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड में धान अधिप्राप्ति हेतु 80-85 हजार क्विंटल धान की खरीद की गयी है, जिसमें अभीतक 50-55 क्विंटल धान ही राईस मिलों को मिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वजीरगंज के श्री रामानुग्रह उच्च विद्यालय के खुले मैदान में हजारों क्विंटल धान पड़े हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सड़ रहे धान को बचाने एवं संबंधित दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*359. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के कसबा नेहरू चौक, कसबा रेलवे स्टेशन से रेलवे गुमटी तक सड़क 15 वर्षों से अत्यंत ही जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*360. श्री आनन्दी प्रसाद यादव––क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के सिक्टी, पलासी, कुर्साकांटा प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित पशु चिकित्सालय तथा कुर्साकांटा प्रखंड के हलधरा हाट पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालयों में कबतक पशु चिकित्सक का पदस्थापन करने का विचार रखती है ?

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*361. डॉ0 अरूण कुमार––क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी–बख्तियारपुर प्रखंड, सलखुआ, महिषी, नवहट्टा, बाढ़ प्रभावित प्रखंड है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाढ़ प्रभावित होने के कारण उक्त प्रखंडों के लोगों को लौहयुक्त एवं गंदा पानी पीना पड़ता है, जिससे तरह–तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आदेश का अनुपालन

*362. श्री राजेश्वर राज––क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज नगर पंचायत में जल निकासी हेतु जिलाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदन पत्रांक 775, दिनांक 06 नवम्बर, 2012 के आधार पर नाला एवं जलापूर्ति योजना का विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कर समर्पित करने हेतु तत्कालीन मंत्री द्वारा पत्रांक 382, दिनांक 07 मार्च, 2013 द्वारा प्रबंध निदेशक, बिडको, पटना को आदेश दिये जाने के बावजूद अभीतक उसका अनुपालन नहीं होने से जल निकासी एवं जलापूर्ति कार्य ठप है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त आदेश का अनुपालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल की निकासी

*363. श्री विजय कुमार सिन्हा––क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय नगर परिषद् अन्तर्गत वार्ड नं0 2,3,4,5,6,7 सहित लखीसराय जिला समाहरणालय में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, यदि हां, तो उक्त जल निकासी हेतु सरकार की क्या परियोजना है ?

प्रतिनियुक्त करना

*364. श्री मनोहर प्रसाद सिंह––क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत में जलमीनार, वोल्टेज कन्ट्रोलर ठीक है फिर भी पम्प ऑपरेटर की अनुपस्थिति के कारण जलापूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार पम्प ऑपरेटर के अनुपस्थिति के संबंध में कार्यपालक अभियंता, कटिहार को प्रश्नकर्ता द्वारा तीन माह पूर्व पत्र दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार पर पम्प ऑपरेटर की नियमित रूप से प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है ?

लक्ष्य बढ़ाना

*365. डॉ0 अरूण कुमार––क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला में किसानों द्वारा अनुदान पर ट्रैक्टर एवं पम्प सेट क्रय हेतु आवेदन का निपटारा कम लक्ष्य रहने के कारण किसानों की परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषकों के हित में लक्ष्य बढ़ाने का विचार रखती है ?

वितरण कराना

*366. श्री प्रेम रंजन पटेल––क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिलान्तर्गत चानन प्रखंड में उपलब्ध करायी गयी डीजल अनुदान की राशि वर्ष 2012–13 को वितरण नहीं किया जा सका, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वितरण करने का विचार रखती है ?

नोटिस का औचित्य

*367. श्री सुरेन्द्र चंचल––क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंडान्तर्गत फिरोजपुर ग्राम स्थित अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 1985 एवं 1987 में कृषि कार्य हेतु बिना सूद ब्याज के पम्प सेट दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्णयानुसार वर्ष 2007 में किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतु पूर्व में लिये गये 50000 रु0 तक के ऋण को माफ किया जा चुका है, जबकि पम्प सेट प्राप्त करने वाले उक्त ग्राम के अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि विकास बैंक, बखरी (सकरा) द्वारा ऋण अदायगी हेतु मई, 2013 में नोटिस निर्गत किया गया है, यदि हां, तो ऋण माफ किये जाने के बावजूद बैंक द्वारा नोटिस का क्या औचित्य है ?

गाँवों में नक्शा प्राप्त कराना

*368. श्री मंजीत कुमार सिंह––दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 02 जुलाई, 2013 को प्रकाशित छपें खबर "जमीन का नक्शा अब गाँवों में ही" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गाँव की जमीन का नक्शा लेने के लिये राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है, यदि हां, तो राज्य के सभी जिलों में "गाँवों में नक्शा प्राप्त कराने की परियोजना" शुरू करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

भुगतान करना

*369. श्री राम नरेश प्रसाद यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंडान्तर्गत 20 (बीस) पंचायतों में वर्ष 2007-08 में 63 प्रगणक से पशु गणना कराया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनवर्षा प्रखंड के पशु प्रगणक के लिये 23 अप्रील, 2011 को विभाग द्वारा 522170.50 रु० प्रखंड को उपलब्ध कराई गई थी;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला नजारत के बेतार संवाद संख्या 581, दिनांक 13 मई, 2011 एवं पत्रांक 583, दिनांक 14 मई, 2011 के माध्यम से राशि शीघ्र लौटाने का आदेश दिया गया था एवं इसके चलते सोनवर्षा से 23 जून, 2011 को संपूर्ण राशि लौटा दी गई और पशु प्रगणक को मानदेय का भुगतान नहीं हो सका;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंडान्तर्गत पशुगणकों को अविलम्ब मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती कराना

*370. श्री जवाहर प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के सासाराम नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्ट्रीट लाइट खराब बंद पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि धर्मशाला चौक, बौलिया मोड़, कुशईच, रोजा रोड, गैस एजेंसी एवं जिला पदाधिकारी के आवास के पास स्थित स्ट्रीट लाइट मरम्मती के अभाव में खराब पड़े हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मती कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

टैक्स वसूलना

*371. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर में वर्तमान में साढ़े तीन लाख मकान निर्मित हैं, जिसमें लोग आवासित हैं तथा मात्र दो लाख आवासों द्वारा ही होल्डिंग टैक्स दिया जा रहा है, जिससे पटना नगर निगम को प्रतिवर्ष राजस्व की काफी हानि हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार शेष 1.5 लाख आवासों से होल्डिंग टैक्स वसूलने हेतु कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है ?

कार्य शुरू करना

*372. श्री श्रवण कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखंडान्तर्गत प्रस्तावित कोशियावां ग्रामीण जलापूर्ति योजना का प्राक्कलन क्षेत्रीय अभियन्ता, पटना प्रक्षेत्र द्वारा पत्रांक 997, दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भेज दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना हेतु जमीन चिन्हित कर कतला परिषद्, नालन्दा द्वारा पत्रांक 25, दिनांक 8 फरवरी, 2013 से अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, हिलसा को भेज दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोशियावां ग्राम में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य शीघ्र शुरू करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लाभान्वित कराना

*373. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राष्ट्रीय ''मछुआ आवास योजना'' के तहत वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक 12,300 आवासों का लक्ष्य निर्धारित रहा है;

(2) क्या बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखंड अन्तर्गत महुआवां, बखरी, बड़हरवा, सीवान, खरूहा, झौआराम, मलाही टोला, जमुआ तथा घोड़ासहन प्रखंड अन्तर्गत भलुअहिया, पीठवा आदि मछुआ बहुल ग्राम है जो ''मछुआ आवास योजना'' से वंचित है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित ग्रामों के मछुआ वर्ग को ''मछुआ आवास योजना'' से लाभान्वित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*374. श्री भोला राय--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कदवां प्रखंड अन्तर्गत श्री पूर्णिमा देवी गोशाला, सोनैली अत्यंत पुराना एवं राज्य के पंजीकृत गोशाला है, परन्तु इसकी अधिकांश भूमि अतिक्रमित है, यदि हाँ, तो उक्त भूमि को सरकार अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है ?

पुनः नियोजित करना

*375. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे प्रदेश में वर्ष 2010-11 में विषय-वस्तु विशेषज्ञों को नियोजित किया गया था एवं वर्ष 2013-14 में पद मुक्त कर दिया गया है, जिससे कृषि विभाग के सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में काफी परेशानी हो रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पद से हटाये गये विषय-वस्तु विशेषज्ञों को पुनः नियोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कार्य प्रारंभ कराना

*376. श्री गोपालजी ठाकुर--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में किसान भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति एक वर्ष पूर्व दिया गया है, परन्तु अभीतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है ?

पटनाः
दिनांक 1 अगस्त, 2013 (ई०) ।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 47--डी०टी०पी०--450